

### **Plight of potato growers in the country**

**श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र):** उपसभापति महोदय, देश के 80 लाख आलू उत्पादक किसानों की समस्या को उजागर करने के लिए मैंने यह मुद्दा यहाँ उठाया है। आलू उत्पादक आज अभूतपूर्व संकट में हैं। बिहार जैसे प्रदेशों में फसल नहीं आयी, इसलिए संकट है और उत्तर प्रदेश, बंगाल और अन्य प्रदेशों में अच्छी फसल आयी, लेकिन फिर वे संकट में हैं। यहाँ तक कि बंगाल में दो किसानों ने आत्महत्या कर ली है। यह इसलिए हुआ है कि फसल का दाम नहीं मिल रहा है। ग्राहक को तो इसके लिए 20-25 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं, लेकिन किसान को एक या दो रुपया ही मिल पा रहा है। यह लाभकारी मूल्य नहीं है, यह तो कोई भी मानेगा, लेकिन यह उत्पादन के खर्च की भरपाई भी नहीं है। उत्पादन खर्चा भी इससे बहुत ज्यादा है। इससे तो वहन और कोल्ड स्टोरेज में रखने का खर्चा तक नहीं निकलता है। इसीलिए किसानों ने कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालना ही बंद कर दिया और इसे वहीं छोड़ रहे हैं। इससे स्टोरेज वाले भी संकट में हैं। यह कैसे होता है? इसके बारे में मेरी यह राय है कि यह दो ही कारणों से होता है — एक, सरकार की नीति के कारण और दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज में चल रहे सट्टे के कारण।... (व्यवधान)... मैं वही बता रहा हूँ। आलू का 34 मिलियन टन उत्पादन हो रहा है, लेकिन सट्टे का खेल 340 मिलियन टन का हो रहा है, यानी दस गुना ज्यादा ट्रेड हो रहा है, लेकिन डिलीवरी केवल एक परसेंट है। अगर पिछले दो साल का रिकार्ड देखें तो यह पता चलता है कि फरवरी से अप्रैल तक इसके दाम घटे रहते हैं और अप्रैल के बाद दाम चढ़ते हैं। इस साल भी यही हो रहा है। क्या सरकार तमाशबीन बन कर देखती रहेगी? किसान के प्रति उसकी कोई प्रतिबद्धता है या नहीं? इसलिए मेरी चार मांगें हैं। मेरी पहली मांग यह है कि आलू को MSP नहीं देते हैं, लेकिन यह क्यों नहीं देते हैं? ऐसे बहुत सारी रोजमर्रा की चीजें हैं, जिनका उत्पादन न होने पर लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन उत्पादन करने वाला कभी अकाल के कारण और कभी ज्यादा फसल आने के कारण घाटे में जाता है।

इसलिए मेरी पहली मांग यह है कि आलू जैसे पदार्थों के लिए भी MSP होना चाहिए। मेरी दूसरी मांग यह है कि जिनका भी नुकसान हुआ है, अगर महाराष्ट्र में मुआवजा मिलती है, तो दूसरी जगहों पर भी मिलना चाहिए। मेरी तीसरी मांग यह है कि forward exchange में जो सट्टेबाजी हो रही है, उस पर लगाम लगाने का कोई उपाय सोचना चाहिए। मेरी चौथी मांग यह है कि कोई price band का mechanism आए, जो यह देखे कि ग्राहक को वह वस्तु कितने दाम में मिलेगी और उत्पादन खर्च निकालकर, किसान के लिए लाभकारी मूल्य कैसे सुनिश्चित होगा। धन्यवाद।

### **Death of a passenger in Nizamuddin-Kochi Duronto Express due to lack of proper medical facilities**

**SHRI P. RAJEEVE (Kerala):** Thank you, Sir. I would like to raise the issue of non-availability of medical facilities in the newly-introduced Duronto trains. Three days back, one passenger died in the Nizamuddin-Kochi Duronto Express. The deceased, Kumaran, complained of chest pain and uneasiness. The co-passengers informed the T.T. who was sitting in the A.C. compartment. Nobody from Railways came to his help. They were informed that there was no doctor in the train itself. Even the paramedical staff was not available. Sir, if such a condition prevails, what would be the fate of the passengers who are traveling in nonstop long distance trains. While answering to the Question No. 403, the hon. Railway Minister stated that, "The present status of provision of essential services like medical, communication and catering in trains is as under. Medical facility of a doctor with paramedical staff has been provided in all Duronto trains as a pilot project. Further

extension of this service would be considered on the outcome of this pilot project". But the reality is far away from this answer. No doctor is available in the Nizamuddin-Kochi Duronto Express. Actually, in Malayalam, there is a word 'Duronto' which means disaster. Since the introduction of this service, all passengers have been facing a disastrous situation in this train. I would say, the hon. Railway Minister mislead not only this House but the total railway commuters of this country. So, I urge upon the Government to think over this and provide, at least, minimum medical facilities in the Nizamuddin-Kochi Duronto Express. Thank you, Sir.

PROF. P.J. KURIEN (Kerala): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): उपसभापति जी, मैं अपने आपको इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI P. KANNAN (Puducherry): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI D. RAJA (West Bengal): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Employees' State Insurance (Amendment) Bill, 2010. ...*(Interruptions)*...

SHRI TARINI KANTA ROY (West Bengal): Sir, I have given a notice. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... You see, you cannot raise it here. Once your notice has not come, it means, it has not been admitted. ...*(Interruptions)*...

SHRI TARINI KANTA ROY: No, no, Sir, I have given a notice earlier. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Fine, but it has not been admitted. ...*(Interruptions)*...

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, indiscriminate firing is going on ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It has to be admitted. ...*(Interruptions)*... You can take it up ...*(Interruptions)*... The Chairman has not admitted ...*(Interruptions)*... Whatever has been admitted, I have taken up. ...*(Interruptions)*... Please, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI TARINI KANTA ROY: This is a very serious issues, Sir. ...*(Interruptions)*...

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, firing is going on. *(Interruptions)* This is a very serious issue, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I cannot allow anything in the Zero Hour which has not been admitted. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... The Employees' State Insurance (Amendment) Bill, 2010. Shri Mallikarjun Kharge.

-----